EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 16 December 2025

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त कर नए विधेयक की तैयारी

मनरेगा अब 'जी राम जी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

सरकार 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) को निरस्त करने और इस संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लेकर आ सकती है। इस विधेयक का नाम 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत (वीबी) - जी राम जी) विधेयक, 2025' होगा। इस विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांटी गई हैं। इस विधेयक पर कार्य मंत्रणा समिति में भी चर्चा हुई है, जहां पर कुछ सदस्यों ने इसे सदन की समिति को भेजने की भी मांग की है। इस विधेयक को सदन समिति को भेजने का फैसला सदन पर छोड़ा गया है।

सोमवार को यह विधेयक सदन पटल पर पेश नहीं किया गया और सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को पहली सूची में यह विधेयक मसविदे में शामिल नहीं था और इस विधेयक के लिए अलग से मसविदा लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया था। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किया जाना था।

कार्य सूची में बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप 'ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी।

विधेयक के उद्देश्यों में शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा ने पिछले 20 साल से अधिक समय तक ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि, सामाजिक सुरक्षा के बड़े पैमाने पर कवरेज और बड़ी सरकारी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने से ग्रामीण इलाकों में जो बड़ा सामाजिक-आर्थिक बदलाव आया है, उसे देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी हो गया है।

सांसदों ने की है मांग संसद समिति को भेजा जाए विधेयक। *सोमवार* को लोकसभा में नहीं हुआ पेश, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान लेकर आए हैं विधेयक।

प्रमुख बदलाव

गारंटीकृत वेतन रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाई गई, अब 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, 25 फीसद रोजगार बढ़ेगा।

केंद्र सरकार वीबी-जी राम जी के वित्तपोषण का भार साझा करेगी। सरकार पूरी मजदूरी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वीबी-जी राम जी योजना के तहत राज्यों को मजदूरी भुगतान का भार साझा करना होगा।

श्रम बजट के स्थान पर मानक आवंटन : राज्यों को असीमित निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वीबी-जी राम जी विधेयक की धारा 4 (5) के अनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होगा।

कृषि मौसम के दौरान रोजगार गारंटी में विराम। वीबी-जी राम जी विधेयक में कृषि के चरम मौसमों के दौरान रोजगार गारंटी को स्थगित करने का प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान का उद्देश्य कृषि के चरम मौसमों के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वीबी-जी राम जी-बिल में श्रमिकों को हर हफ्ते मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है।

यदि रोजगार नहीं दिया, तो राज्य को अनिवार्य तौर बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

मनरेगा में जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था। नए विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तीकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है, और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' पर जोर देना है।

राज्य पर बोझ पड़ेगा : तेदेपा

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (ब्यूरो)।

केंद्र सरकार के विकसित भारत ज़ रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 में योजना के वित्तपोषण को साझा करने के प्रावधान के कारण राज्यों के खजाने पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है। इस पर आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा है कि वे इसका समर्थन और कार्यान्वयन करेंगे, हालांकि वित्तपोषण का बंटवारा चिंताजनक है और इससे राज्य पर बोझ पड़ेगा।

आंध्र प्रदेश के वित्त, योजना और विधायी मामलों के मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करेगी और इसका समर्थन व कार्यान्वयन करेगी।

नाम हटाया जाना राष्ट्रपिता का अपमान : विपक्ष

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (ब्यूरो)।

विपक्ष ने मनरेगा के स्थान पर नया कानून बनाने की तैयारी के बीच सोमवार को कहा कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। उसने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का कदम महात्मा गांधी का अपमान है। सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों, स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं।

-पूरी खबर पेज 13

Jansatta Page No-1

अनुमान

ओखला पक्षी विहार में इस बार पक्षी विशेषज्ञों से गणना कराएगा वन विभाग

तापमान में देरी से गिरावट, कम हो सकती है प्रवासी पक्षियों की संख्या

आशीष दुबे
नोएडा, 15 दिसंबर।

दिल्ली से कालिंदी कुंज के रास्ते यमुना का पुल पार करते ही पक्षियों का कलरव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। लेकिन इस मर्तबा पक्षियों की चह-चहाहट कम है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार तापमान में गिरावट देरी से आई है, इस वजह से फिलहाल प्रवासी पक्षियों की संख्या कम है। आने वाले दिनों में इनमें कितना इजाफा होगा, यह तापमान के गिरावट पर भी निर्भर करेगा।

कुछ दिनों से तापमान में गिरावट के साथ यमुना से सटा नोएडा का ओखला पक्षी विहार पक्षी प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहां प्रवासी

फाइल फोटो

प्रभागीय वन विभाग के रेंजर अमित गुप्ता ने जनसत्ता को बताया कि गत वर्ष यहां पक्षियों की करीब 18-20 हजार तक की गणना की गई थी। हालांकि यह गणना पक्षी विशेषज्ञों से नहीं कराई गई थी। इस बार गणना पक्षी विशेषज्ञों से कराने की योजना है, ताकि वास्तविक संख्या का मालूम की जा सके। सर्दियों में पक्षी विहार खुलने का समय सुबह साढ़े सात और बंद होने का समय शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए यहां छह ई कार्ट उपलब्ध हैं। जिन्हें किराए पर लिया जा सकता है। फिलहाल लोगों की संख्या कम रहने की वजह से तीन ई कार्ट चलाए जा रहे हैं। 25 दिसंबर के बाद से सभी छह ई कार्ट चलने शुरू हो जाएंगे।

इस पक्षी विहार में हर साल यूरोप, साइबेरिया, कनाडा समेत मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से हजारों की संख्या में पक्षी पहुंचते हैं। जिनमें कामनटील, ग्रेलेज गूज, नार्दन शेवलर, कामन कूट और ब्लैक हेडेड आइबिस आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा देशी पक्षी जैसे पेलिकन, सारस, बगुले, बत्तख, किंगफिशर और काली गर्दन वाला सारस आदि भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं।

पक्षियों की करीब एक दर्जन ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों ने अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल यहां करीब सात हजार पक्षियों की संख्या आंकी जा रही है, जिसके जनवरी की शुरुआत तक दो गुना से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। प्रभागीय वन विभाग के रेंजर अमित गुप्ता ने जनसत्ता को बताया कि गत वर्ष यहां पक्षियों की करीब 18-20 हजार तक की गणना की गई थी। हालांकि यह गणना पक्षी विशेषज्ञों से नहीं कराई गई थी। इस बार गणना पक्षी विशेषज्ञों से कराने की योजना है, ताकि वास्तविक संख्या का मालूम की जा सके। सर्दियों में पक्षी विहार खुलने का समय

Jansatta Page No-4

जानें-समझें

आर्थिक विरोधाभास

जीडीपी में आगे, पर नौकरियों में पीछे क्यों

जनसत्ता संवाद

भारत में वर्ष 2025 में आर्थिक विरोधाभास की तस्वीर सामने आई है। एक ओर, लगातार सात फीसद से अधिक की सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) की दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपनी स्थित मजबूत की है। दूसरी ओर, दीर्घकालिक बेरोजगारी के संकट को लेकर बहस तीखी हुई है। लाखों शिक्षित और आकांक्षी युवाओं (जो या तो बेरोजगार हैं या जिन्हें अपने कौशल के मुताबिक रोजगार नहीं मिला है) के लिए अर्थव्यवस्था के आंकड़े खोखले साबित हो रहे हैं। साथ ही, जमीनी स्तर पर विकास और वास्तविक रोजगार के मौकों के बीच अंतर भारत के विकास, सामाजिक संतुलन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अहम चुनौतियों में से एक है।

कहां है समस्या

समस्या बड़ी है। हर साल 1.2 करोड़ से ज्यादा युवा भारत के श्रम बल में शामिल होते हैं। 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआइई) और सरकार के 'पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे' (पीएलएफएस) के ताजा आंकड़ों से लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर की तस्वीर उजागर हुई है। ये न केवल रोजगार मुहैया कराने का मामला है, बल्कि कामगारों की मांग और आपूर्ति के बीच घोर अंतर का मामला भी है। इसके पीछे कई संरचनात्मक कारक हैं।

तकनीक की दोधारी तलवार

तकनीक और खासकर बहुचर्चित कृत्रिम मेधा (एआइ) से वे उद्योग बदल रहे हैं जो कभी बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम करते थे। आइटी, बैक आफिस और निर्माण उद्योग को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों से चुनौती मिल रही है, जहां अधिक कौशल वाले रोजगारों का सृजन हुआ है। इसके अलावा कम हुनर वाली नौकरियों में कटौती हो रही है।

निर्माण उद्योग का हाल

श्रमिकों को खेती की जगह रोजगार प्रधान निर्माण उद्योग (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) की तरफ ले जाने के पारंपरिक विकास माडल को लागू करने में भारत को अरसा लगा है।

(फाइल फोटो)

भारत को 21वीं शताब्दी के लायक श्रम कानून की रूप-रेखा की आवश्यकता है। ऐसा कानून जो लचीलेपन की आवश्यकता और कामगारों के सुरक्षा अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत करनी होगी और कामगारों को स्वास्थ्य, बीमा और पेंशन से जुड़े लाभ मुहैया कराने होंगे इसके दायरे में गिग और अनौपचारिक कामगार भी शामिल होने चाहिए। - *राधिका कपूर, वरिष्ठ रोजगार विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन*

चुनौती विशाल है, लेकिन अवसर भी उतना ही बड़ा है। अस्थिरता का खतरा उत्पन्न करने वाली जनसंख्या आने वाले दशकों में भारत को आर्थिक मामलों में दिग्गज देश बना सकती है। श्रम प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को मजबूत करने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को लगभग आठ फीसद पर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। - *मनीष सभरवाल, उपाध्यक्ष, 'नेशनल काउंसिल आफ अप्लायड इकोनामिक रिसर्च'*

कैसे निकले राह

संकट का समाधान करने के लिए भारत की आर्थिक नीति में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। लक्ष्य समावेशी ढंग से अर्थव्यवस्था को विकसित करने की तरफ होना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले हैं। इस क्षेत्र को आसानी से कर्ज, तकनीक और औपचारिक बाजार मिलना चाहिए। कौशल से जुड़ी पहल को आपूर्ति केंद्रित होने के बदले मांग आधारित बनाना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के जरिए शिक्षा से रोजगार तक सीधा रास्ता तैयार करना होगा। साथ ही, जिन क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार है, वहां रणनीतिक नीतिगत समर्थन देना चाहिए। इसमें न केवल कपड़ा और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं बल्कि उभरता हरित क्षेत्र भी है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर कूड़ा प्रबंधन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों निर्माण तक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बदलाव से नौकरियों के लिए बड़े अवसर हैं।

अब इस क्षेत्र में जूझना पड़ रहा है, जबकि पूर्वी एशिया के देश सफलतापूर्वक इस रास्ते पर चल रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने 60 के दशक में निर्यात आधारित उद्योगीकरण को अपनाकर उद्योगों को बढ़ावा दिया। चीन ने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज (टीवीई) के जरिए गांवों के अतिरिक्त श्रमिकों को इकट्ठा किया, जिससे निर्माण क्षेत्र सीधे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा। भारत में 'मेक इन इंडिया' और 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआइ) जैसी पहल के बावजूद जीडीपी और उससे भी बढ़कर रोजगार में निर्माण का हिस्सा कम रहा है। ज्यादा ध्यान पूंजी-प्रधान उद्योगों जैसे कि इलेक्ट्रानिक्स और असेंबलिंग इकाई पर रहा है।

कौशल की कमी

भारत की शिक्षा प्रणाली नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने में नाकाम है। नौसकाम की एक रपट में कहा गया है कि उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल- जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा एनालिटिक्स और ग्रीन-टेक विशेषज्ञता - और स्नातक करने वालों के कौशल में खासा अंतर है। ऐसे में, उद्योग शिकायत करते हैं कि प्रतिभाओं की कमी है। जबकि लाखों पढ़े-लिखे छात्र बेरोजगार हैं।

संतुलन की जरूरत

भारत के लगभग 90 फीसद कामगारों को नौकरी देने वाला अनौपचारिक सेक्टर झटकों को झेलने का काम करता है। लेकिन यह अनिश्चितता प्रदान करता है। इस सेक्टर की नौकरियों में कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी की स्थिति होती है। जानकारों के मुताबिक, अप्रेंटिसशिप के जरिए शिक्षा से रोजगार तक सीधा रास्ता तैयार करना होगा। साथ ही, भारत को 21वीं शताब्दी के लायक श्रम कानून की रूप-रेखा की आवश्यकता है। ऐसा कानून, जो लचीलेपन की आवश्यकता और कामगारों के सुरक्षा अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करे।

Jansatta Page No-7

सम-सामयिक

हिंद-प्रशांत : भारत और फ्रांस में बढ़ रही साझेदारी

जनसत्ता संवाद

वर्ष 2025 में जिस तरह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि फ्रांस यहां अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। चीन और अमेरिका के बाद यूरोपीय देश भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामरिक समीकरणों में महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। इस काम में फ्रांस को भारत की मदद चाहिए।

वर्ष 2025 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की उपस्थिति की शुरुआत धमाकेदार रही। रफाल लड़ाकू विमानों ने फ्रांसीसी विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गाल से उड़ान भरते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया। इसे 'मिशन क्लेमेंसो' नाम दिया गया, जो 20वीं सदी के शुरुआती फ्रांसीसी राजनयिक जार्जेस क्लेमेंसो के नाम पर आधारित है। क्लेमेंसो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान एशिया आए थे और जीत हासिल की थी। हिंद-प्रशांत में करियर स्ट्राइक ग्रुप (सीएसजी) की तैनाती फ्रांस की बड़ी उपलब्धि है। इसमें चार्ल्स डी गाल और उसके 22 रफाल के अलावा, चार फ्रिगेट, एक आपूर्ति जहाज, एक परमाणु हमलावर पनडुब्बी और कुछ समुद्री गश्ती विमान भी शामिल थे।

साठ के दशक के बाद पहली बार, सीएसजी ने प्रशांत महासागर में जाकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से साझेदारों और सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया। हिंद महासागर में ला पेरूज अभ्यास के दौरान फ्रांसीसी नौसेना और भारत सहित आठ क्षेत्रीय साझेदारों ने संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने का प्रशिक्षण लिया। अरब सागर में, सीएसजी ने पहली बार भारतीय नौसेना के साथ आइएनएस विक्रांत के साथ द्विपक्षीय अभ्यास 'वरुण' के 23वें संस्करण में हिस्सा लिया। वायु, सतह और पानी के नीचे ये अब तक का सबसे जटिल अभ्यास था।

कूटनीतिक प्रभाव सबसे अच्छी तरह तब देखने को मिला, जब सीएसजी के बंदरगाह पर आने के कुछ ही हफ्तों बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। सिंगापुर के शांगरी-ला संवाद में उनका भाषण नौसैनिक कूटनीति की पहलों का नतीजा था। मैक्रों द्वारा यूरोप और एशिया के बीच गठबंधन का आह्वान गुटनिरपेक्षता पर जोर माना गया। मैक्रों ने चीन को संदेश भी दिया। फ्रांस हमेशा से ताइवान और फिलीपींस में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों का आलोचक रहा है, लेकिन साथ ही अमेरिकी दखल का भी विरोध करता है।

दूसरी ओर, भारतीय नौसेना, महासागर मिशन के माध्यम से, नियमित रूप से इस क्षेत्र में तैनात रहती है और फ्रांस की सेना के साथ मिलकर मजबूत सुरक्षा प्रदाता का काम करती है। भारत और फ्रांस की इस नौसैनिक क्षमता को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूदा 'फ्रांज' पहल के समान एक बेहतर तंत्र माना गया। सवाल है कि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस और क्या-क्या कर सकता है? फ्रांस समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनामी और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में भारत के साथ बेहतर ढंग से सहयोग कर सकता है, क्योंकि दोनों देश 2026 में बहुराष्ट्रीय निकायों की अध्यक्षता साझा कर रहे हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अहम हैं। चर्चा के लिए सबसे बेहतर समय अगले साल होगा। मैक्रों जनवरी 2026 में भारत आने वाले हैं। तब भारत द्वारा आयोजित एआइ एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सह-अध्यक्ष के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति भाग लेंगे।

निगरानी में सहयोग

फ्रांस-भारत सहयोग समुद्री सुरक्षा व ब्लू इकोनामी में बढ़ सकता है। जो देश इच्छुक हैं, उनके सहयोग से फ्रांस और भारत क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में कमियों को दूर कर सकते हैं। हवाई निगरानी मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है। फ्रांस के पास ला रीयूनियन में कोई समर्पित गश्ती विमान नहीं है और भारत के पी-8 विमान सिर्फ गोवा और तमिलनाडु में तैनात हैं। अगालेगा और डिएगो गार्सिया तक भारतीय हवाई पहुंच का विस्तार करके और नियमित निगरानी विमान तैनात करके इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

Jansatta Page No-7

पुतिन ने भारत के साथ सैन्य समझौते को संघीय कानून के तौर पर मंजूरी दी

रसद को भी विनियमित करेगा। डूमा की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोट में, रूसी मंत्रिमंडल ने कहा कि इस दस्तावेज की स्वीकारोक्ति से दोनों देशों के हवाई क्षेत्र का आपसी इस्तेमाल आसान होगा और रूसी तथा भारतीय युद्धपोतों के लिए 'पोर्ट काल' भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा, यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मज़बूत करेगा। दोनों देशों के बीच पुष्टि के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद यह अहम सैन्य समझौता लागू होगा।

Jansatta Page No-8

भारत ने मेक्सिको को दिया तरजीही व्यापार करार का प्रस्ताव

दक्षिण अमेरिकी देश के ऊंचे आयात शुल्क से घरेलू निर्यातकों को राहत दिलाने के लिए उठाया कदम

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा)।

मेक्सिको के ऊंचे आयात शुल्क से घरेलू निर्यातकों को राहत दिलाने के लिए भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश के साथ एक तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) का प्रस्ताव रखा है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मेक्सिको ने उन देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर लगभग पांच फीसद से लेकर 50 फीसद तक आयात शुल्क लगाने का फैसला किया, जिनके साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यह शुल्क 1,463 श्रेणियों पर लागू होंगे और इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत ने मेक्सिको के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि तकनीकी स्तर पर बातचीत चल रही है। आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता तरजीही व्यापार समझौते का प्रयास करना है, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने में काफी समय लगेगा। इसलिए हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अग्रवाल ने बताया कि जहां एफटीए में दो व्यापारिक साझेदार अधिकतम उत्पादों पर आयात शुल्क को काफी हद तक कम या समाप्त कर देते हैं, वहीं तरजीही व्यापार समझौते में सीमित संख्या में उत्पादों पर शुल्क घटाए या हटाए जाते हैं। मेक्सिको के व्यापारिक साझेदार ऊंचे शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि ये शुल्क विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप हैं।

मेक्सिको ने उन देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर लगभग पांच फीसद से लेकर 50 फीसद तक आयात शुल्क लगाने का फैसला किया, जिनके साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

उन्होंने कहा कि ये शुल्क निर्धारित सीमा दरों के भीतर हैं और इनका मुख्य लक्ष्य भारत नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि हमने पीटीए का प्रस्ताव इसलिए रखा है क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ के अनुरूप आगे बढ़ने का एक तरीका है। हम एक पीटीए कर सकते हैं।

'अमेरिका के साथ समझौते की रूपरेखा अंतिम दौर में'

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा)।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के 'बेहद करीब' हैं और दोनों देश इस मामले में सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश उच्च शुल्क से निपटने के लिए व्यापार समझौते की रुपरेखा तैयार करने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अलग-अलग वार्ताएं कर रहे हैं।

अमेरिका के नए उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर, वाणिज्यिक सचिव के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए पिछले सप्ताह यहां पहुंचे थे। स्विट्जर की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर गौर किया और समझौते एवं व्यापक बीटीए की बातचीत की प्रगति की समीक्षा की। अग्रवाल ने कहा कि हम समझौते की रूपरेखा तैयार करने के बेहद करीब हैं, जिसे हम मानते हैं कि कम समय में पूरा किया जा सकता है। हालांकि मैं इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताना चाहूंगा। बीटीए और औपचारिक दौर की बैठकें होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि अंतिम चरण की वार्ता में आमतौर पर ऐसे दौर की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूजीलैंड के साथ जारी वार्ता का उदाहरण देते हुए सचिव ने कहा कि जब हम एक ऐसे दौर में होते हैं, जहां कुछ ही मुद्दे या क्षेत्र सुलझाने बाकी होते हैं तो औपचारिक वार्ताओं का कोई दौर नहीं होता। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ हम वार्ता को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन इस पर बात होती है। अग्रवाल ने कहा कि बातचीत का अंतिम चरण सबसे कठिन होता है।

'अमेरिका को महंगे बासमती चावल का करते हैं निर्यात'

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत अमेरिका को मुख्य रूप से महंगे बासमती चावल का निर्यात करता है लिहाजा भारतीय चावल की अमेरिकी बाजार में डंपिंग करने का कोई मामला ही नहीं बनता है। अग्रवाल ने नवंबर महीने के व्यापार आंकड़ों पर कहा कि भारतीय चावल पर अमेरिका में पहले से ही 50 फीसद सीमा शुल्क लागू है। हम मुख्य रूप से अमेरिका को बासमती चावल का निर्यात करते हैं, जो एक जीआइ (भौगोलिक संकेतक) उत्पाद है। हमारे कुल निर्यात का 80 फीसद से अधिक हिस्सा बासमती चावल का है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे बासमती चावल की कीमतें सामान्य निर्यात कीमतों से कहीं अधिक हैं, लिहाजा डंपिंग का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

Jansatta Page No-10

रुपया 29 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.78 प्रति डालर पर

मुंबई, 15 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 29 पैसे फिसल कर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.78 प्रति डालर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते रुपए में गिरावट आई। एक समय यह अमेरिकी डालर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 90.80 तक आ गया था।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि जोखिम से बचने की धारणा और आयातकों की मजबूत डालर मांग ने निवेशकों की धारणाओं को और कमजोर किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 90.53 पर खुला, लेकिन बाद में

भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते रुपए में गिरावट आई।

फिसलते हुए कारोबार के दौरान 90.80 के रेकार्ड निचले स्तर तक पहुंच गया, जो उसके पिछले बंद भाव से 31 पैसे की गिरावट है। कारोबार में अंत में यह 29 पैसे टूटकर 90.78 के रेकार्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।

भारतीय मुद्रा शुक्रवार को 17 पैसे गिरकर 90.49 पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि रुपया रेकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और एशियाई मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है।

Jansatta Page No-10

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में जॉर्डन पहुंचे, भारतीय समुदाय ने पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया

तीन देशों की यात्रा कई मायनों में अहम, पाक के लिए भी संदेश

विश्लेषण

■ मदन जैड़ा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तीन में से दो देश जॉर्डन और ओमान इस्लामिक देश हैं तथा इस्लामिक देशों के संगठन के सदस्य भी हैं। इथोपिया में भी खासी मुस्लिम आबादी है लेकिन यह देश भारत की ग्लोबल साउथ नीति के नजरिये से महत्वपूर्ण है।

वैश्विक कूटनीति के हिसाब से इस यात्रा को इस्लामिक देशों के साथ रिश्तों को लगातार मजबूत बनाने की भारत की दूरगामी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस्लामिक देशों की यात्राएं कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए भी संदेश है।

मोदी को सबसे ज्यादा सम्मान इस्लामिक देशों से मिले : जेएनयू के प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि मोदी की इस्लामिक देशों की यात्रा न सिर्फ पाकिस्तान को अलग-थलग करती है। बल्कि देश के मुस्लिमों में भी नकारात्मक संदेश को दूर करती है। प्रधानमंत्री मोदी को आज तक विदेशों में जितने भी सम्मान मिले हैं, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम देशों ने दिए हैं। इसलिए इस्लामिक देशों के रिश्तों को मजबूत बनाना भारत की कूटनीति है, जो बेहद सफल हुई है। आज पाकिस्तान इस्लामिक देशों के बीच भी अलग-थलग सा पड़ गया है। हाल में पाक और सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया था कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना उद्देश्य: अफ्रीकी देश इथोपिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और भारत हमेशा ग्लोबल साउथ देशों की आवाज उठा रहा है। जी-20 में अफ्रीकी संघ की एंट्री भी भारत के प्रयासों से हुई। दरअसल, भारत की रणनीति छोटे देशों चाहे वे इस्लामिक देश हों या फिर ग्लोबल साउथ के देश, उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना है। ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी होने जा रहा है।

तीनों देशों के साथ काफी पुराने रिश्ते: जॉर्डन रवाना होने से पूर्व जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों ऐसे देश हैं, जिनके साथ भारत के व्यापक समकालीन द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पुराने और सांस्कृतिक संबंध हैं।

जॉर्डन के अम्मान में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। • एएनआई

दोनों देशों के बीच 2.87 अरब डॉलर का कारोबार

2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.87 अरब डॉलर रहा। भारत जॉर्डन को 1.46 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। भारत का जॉर्डन में लगभग 1.5अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। दोनों देशों के बीच व्यापार-आर्थिक संयुक्त समिति और विभिन्न कार्य समूह जैसे संस्थागत तंत्र बातचीत को आसान बनाते हैं।

भारत और जॉर्डन के बीच व्यापार

आंकड़े अरब डॉलर में

शिक्षा-सांस्कृतिक संबंध भी गहरे

लगभग 2,500 जॉर्डन के पूर्व छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं और लगभग 500 जॉर्डन के छात्र वर्तमान में भारत में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय कला, संगीत और सिनेमा के प्रति जॉर्डन में भारी उत्साह है।

मोदी और किंग अब्दुल्ला के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा

अम्मान, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात की।

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देश करीबी समन्वय बनाए रखेंगे। उन्होंने गाजा संकट पर किंग अब्दुल्ला की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका की सराहना की। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख साझा और स्पष्ट है।

पीएम हसन ने स्वागत किया : इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे। हवाईअड्डे पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

अम्मान में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जार्डन के शाह अब्दुल्ला से की मुलाकात, बोले

आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख एक जैसा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने सोमवार को यहां मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा पारस्परिक महत्त्व के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर मोदी दो दिवसीय यात्रा पर जार्डन पहुंचे। शाह ने मोदी का हुसैनीया पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले दोनों के बीच आमने-सामने की बैठक हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी मुलाकात भारत-जार्डन संबंधों को नई गति प्रदान करेगी और इससे उसमें प्रगाढ़ता आएगी। उन्होंने कहा, 'हम व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे।' मोदी ने कहा कि दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ साझा और स्पष्ट सोच है। प्रधानमंत्री ने गाजा मुद्दे पर शाह अब्दुल्ला द्वितीय की 'सक्रिय और सकारात्मक भूमिका' की सराहना की। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम होगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा और स्पष्ट सोच है। आपके नेतृत्व में जार्डन ने आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के खिलाफ दुनिया को एक मजबूत और रणनीतिक संदेश दिया है।' मोदी ने उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जार्डन के शाह का धन्यवाद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आपने भारत-जार्डन संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहद सकारात्मक विचार साझा किए हैं। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह उपलब्धि आने वाले कई वर्षों तक हमें नयी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती रहेगी।' प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा, 'आपके प्रयास न केवल क्षेत्रीय शांति, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में संयुक्त राष्ट्र के इतर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसका जोर हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने पर था। उस समय भी आपने इस विषय पर प्रेरणादायी विचार रखे थे।' मोदी ने कहा कि भारत और जार्डन इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे तथा आपसी सहयोग के सभी अन्य आयामों को और मजबूत करेंगे।

शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि सभी जार्डनवासी आपका (मोदी) जार्डन में पुनः स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच दशकों की मित्रता, आपसी सम्मान और सार्थक सहयोग को दर्शाती है।' उन्होंने कहा, 'हमारे देशों के बीच मजबूत साझेदारी है और हमारे लोगों की समृद्धि को आगे बढ़ाने की साझा इच्छा है। वर्षों के दौरान हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है। आपकी यात्रा आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।'

तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि जार्डन की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। जार्डन की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष हो रहे हैं।

इससे पहले जार्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने हवाई अड्डे पर मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर उनका रस्मी स्वागत किया गया। हसन ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच सहयोग के और व्यापक क्षितिज की ओर देख रहे हैं, विशेष रूप से आर्थिक, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में। जब मोदी होटल पहुंचे, तो जार्डन में भारतीय समुदाय के लोगों और भारत के मित्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन।

प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी मुलाकात भारत-जार्डन संबंधों को नई गति प्रदान करेगी और इससे उसमें प्रगाढ़ता आएगी। हम व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे।'

शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि सभी जार्डनवासी आपका (मोदी) स्वागत करते हैं। हमारे देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच दशकों की मित्रता, सम्मान और सहयोग को दर्शाती है।'

समझौतों से सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

जार्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने अम्मान स्थित हुसैनीया पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति देगी और साझेदारी के नए रास्ते खोलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इन समझौतों से भारत और जार्डन के रिश्ते और मजबूत होंगे। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आगामी जार्डन-इंडिया बिजनेस फोरम को लेकर भी उत्साह जताया और कहा कि यह मंच दोनों देशों के बीच व्यापार-से-व्यापार साझेदारी, संयुक्त निवेश और अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण अवसर होगा। उन्होंने इसे एक सार्थक समय पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम बताया।

Jansatta Page No-11

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी विधेयक पेश

विपक्ष के शोरगुल के बीच लोकसभा में पटल पर रखा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की इजाजत संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति जताई। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से 'भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025' सदन में पेश किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल किया।

विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करना है। सिंह ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परमाणु क्षति के लिए एक व्यावहारिक नागरिक दायित्व व्यवस्था तैयार करने सहित परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान करना है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने

विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करना है।

विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा, यह केंद्र सरकार को निजी अनुबंधों में लाइसेंसिंग, नियमन, अधिग्रहण और शुल्क निर्धारण की असीम शक्तियां देता है। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र को अत्यधिक खतरनाक परमाणु क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना और जवाबदेही को सीमित करना, सांविधिक छूट प्रदान करना और न्यायिक उपायों को सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 48 ए का हनन करता है। तिवारी ने कहा, यह विधायिका, कार्यपालिका, नियामक तथा अर्द्ध- न्यायिक शक्तियों को केंद्र सरकार में केंद्रीकृत करता है। इस पर सिंह ने कहा, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस संबंध में जताई गईं ज्यादातर आपत्तियां (विधेयक के) गुण-दोष से संबंधित हैं जिन पर विधेयक पर चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में थोरियम का प्रचुर भंडार है, लेकिन दुर्भाग्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इसका दोहन एवं इस्तेमाल नहीं किया है।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी इस विधेयक का विरोध किया। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा, आज हम विधेयक को पारित नहीं कर रहे हैं, इस पर (आज) विचार करने का प्रस्ताव नहीं है। विधेयक को महज पेश भर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संबद्ध नियम के तहत इस विधेयक को पेश करने की सदन की विधायी क्षमता है।

Jansatta Page No-13

जयशंकर आज इजराइल पहुंचेंगे, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा

यरुशलम, 15 दिसंबर (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को इजराइल पहुंचेंगे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

एक सूत्र ने एजंसी को बताया, 'चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके।' उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी जिस दौरान दोनों नेता बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए।'

जयशंकर राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग व प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे।

पर्यटन मंत्री हाइम काट्ज, अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी डिक्टर और वित्त मंत्री बेजालेएल स्मोट्रिच इस साल पहले भारत गए थे। यह दौरे इसलिए हुए क्योंकि भारत और उनके देश के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है और दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए और फिर पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान एक संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए गए, जो आगे चल कर एफटीए का आधार बनेगा।

Jansatta Page No-11

एथलेटिक्स में बिहार को तीन स्वर्ण सहित चार पदक

अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पाटलिपुत्र खेल परिसर में समापन, अधिकारियों ने किया शानदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पटनाः राष्ट्रीयस्तर की अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हुआ। पाटलिपुत्र खेल परिसर में विभिन्न आयु वर्गों और स्पर्धाओं में 702 पुरुष, 328 महिला और 54 अधिकारियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान कई राज्यों और संस्थानों के खिलाड़ियों ने पदक जीते। चैंपियनशिप से प्रदेश को तीन स्वर्ण और एक रजत पदक मिला। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर गौरवान्वित किया। प्रदेश की अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में स्वर्ण, शिवानी कुमारी ने 1500 मीटर दौड़ में सोना और रिंकी कुमारी ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में सनी कुमार ने स्वर्ण पदक अर्जित किया।

वेटरन पुरुष (40-60 वर्ष) 4×100 मीटर रिले में हरियाणा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि केंद्रीय सचिवालय दिल्ली दूसरे और एनसीटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। महिला (35–60 वर्ष) 4×100 मीटर रिले में उत्तराखंड ने स्वर्ण, केरल ने रजत और केंद्रीय सचिवालय दिल्ली ने कांस्य पदक जीता। पुरुष ओपन ट्रिपल जंप में आरएसबी कोलकाता के प्रदीप ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि एनसीटी दिल्ली के विकास दूसरे और आरएसबी बेंगलुरु के सुमित तीसरे स्थान पर रहे।

रिंकी कुमारी ने दौड़ में जीता रजत : महिला (45-60 वर्ष) 200 मीटर दौड़ में केरल की सुनीता ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार की रिंकी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। तमिलनाडु की मारिया एग्नेस तीसरे स्थान पर रहीं। महिला (35-45 वर्ष) 200 मीटर दौड़ में आरएसबी बेंगलुरु की पवित्रा प्रथम, कर्नाटक की आशालता द्वितीय और गुजरात की रमणी तृतीय स्थान पर रहीं। महिला ओपन 200 मीटर दौड़ में आरएसबी चेन्नई, आरएसबी मुंबई और आरएसबी कोलकाता की टीमों ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष ओपन 200 मीटर दौड़ में आरएसबी मुंबई ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता।

अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते प्रतिभागी। ● जागरण

भाला फेंकती महिला प्रतिभागी। ● जागरण

702 पुरुष, 328 महिला और 54 अधिकारियों ने पदक जीतने के लिए किया परिश्रम

1500 मीटर दौड़, लंबी कूद और भाला फेंक में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीता सोना

दौड़ में बिहार की शिवानी का शानदार प्रदर्शन

बिहार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि महिला ओपन भाला फेंक स्पर्धा में देखने को मिली, जहां बिहार की अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम किया। इस स्पर्धा में आरएसबी बेंगलुरु दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। महिला ओपन 1500 मीटर दौड़ में भी बिहार की शिवानी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र को रजत और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

वेटरन पुरुष (40–60 वर्ष) 4×100 मीटर रिले
हरियाणा, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली, एनसीटी दिल्ली

महिला (35–60 वर्ष) 4×100 मीटर रिले
उत्तराखंड, केरल, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली

पुरुष ओपन ट्रिपल जंप
प्रदीप (आरएसबी कोलकाता)
विकास (एनसीटी दिल्ली)
सुमित (आरएसबी बेंगलुरु)

महिला (45–60 वर्ष) 200 मीटर दौड़
सुनीता (केरल), रिंकी कुमारी (बिहार) मारिया एग्नेस (तमिलनाडु)

महिला (35–45 वर्ष) 200 मीटर दौड़
पवित्रा (आरएसबी बेंगलुरु), आशालता (कर्नाटक), रमणी (गुजरात)

महिला ओपन भाला फेंक
अंजनी कुमारी (बिहार), आरएसबी बेंगलुरु, उत्तराखंड

महिला ओपन 200 मीटर दौड़
आरएसबी चेन्नई, आरएसबी मुंबई
आरएसबी कोलकाता

पुरुष ओपन 200 मीटर दौड़
आरएसबी मुंबई , महाराष्ट्र ,हरियाणा

महिला ओपन 1500 मीटर दौड़
शिवानी कुमारी (बिहार), महाराष्ट्र
केंद्रीय सचिवालय दिल्ली

Dainik Jagaran Page No-III

सरकारी हस्तक्षेप से नहीं, विमानन कंपनियों के अनुशासन से ही सुधरेगा माहौल

पिछले दो हफ्तों के दौरान इंडिगो घटनाक्रम ने एक झटके में भारत के नागरिक उड्डयन सेक्टर की न केवल सांसें उखाड़ दीं बल्कि छवि भी बिगाड़ दी। विरले ही दुनिया के किसी प्रमुख देश में किसी एक एयरलाइन की वजह से आपात जैसी स्थिति बनी हो, जहां बिना किसी पर्याप्त नोटिस के सैकड़ों उड़ानें रद हुई हों, लाखों यात्री बेबस पड़े हों और हर सेक्टर पर प्रतिकूल असर पड़ा हो। उड़ानों के रद होने का सिलसिला अभी भी जारी है हालांकि स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। सरकार की तरफ से सख्ती भी दिखाई जा रही है। पूरे प्रकरण ने एविएशन सेक्टर की नियामक एजेंसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पूरे हालात पर दैनिक जागरण के सहायक संपादक **जयप्रकाश रंजन** ने एविएशन विशेषज्ञ एवं एअर इंडिया के पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर **जितेंद्र भार्गव** से लंबी बातचीत की। पेश हैं साक्षात्कार के प्रमुख अंश :

साक्षात्कार

इंडिगो में नए पायलट भर्ती नहीं हो रहे थे लेकिन सर्दियों के सीजन के लिए ज्यादा उड़ानों की प्लानिंग कैसे कर ली

जितेंद्र भार्गव, एविएशन विशेषज्ञ एवं एअर इंडिया के पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ● स्वयं

● क्या यह पूरा संकट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल की वजह से पैदा हुआ है? गलती कहां हो गई?

संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसके लिए एफडीटीएल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। सबसे पहले तो एफडीटीएल की मांग काफी पुरानी है और यह मांग हवाई जहाजों के पायलटों की तरफ से हो रही थी। इंडिगो एयरलाइन इसके लिए तैयार नहीं थी। मामला हाई कोर्ट गया। कोर्ट के आर्डर से इस नियम को लागू किया गया। इसे पूरी दुनिया में विशेषज्ञ व नियामक एजेंसियां चालकों, क्रू व यात्रियों के लिए सुरक्षित मानती हैं। इसके बाद डीजीसीए को निर्देश गया और उसने एफडीटीएल को दो चरणों में लागू करने का नियम लागू किया। इसके तहत पायलटों और क्रू को ज्यादा आराम देने की व्यवस्था है। नियम लागू होने के साथ ही यह साफ था कि एयरलाइनों को ज्यादा पायलटों की जरूरत होगी। अंतोगत्वा हमें दिसंबर के पहले हफ्ते में जाकर पता चला कि इंडिगो ने नए नियम के मुताबिक पायलटों की भर्ती नहीं की। मेरा मानना है कि जब सरकार की एजेंसी ने नियम लागू कर दिए तो इंडिगो या अन्य कोई भी एयरलाइन यह बहाना नहीं बना सकती कि वह नए पायलटों की भर्ती नहीं कर सकी, इसलिए अचानक ही इतन बड़ा दबाव नहीं सहन कर सकी।

● तो फिर इंडिगो ऐसा क्यों नहीं कर सकी? कंपनी के प्रबंधन की आमतौर पर तो काफी तारीफ होती रही है?

इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इंडिगो से जुड़े लोग ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस कंपनी के पास एविएशन सेक्टर की 65 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी है। देश की अन्य एयरलाइनों के स्तर पर गलती हुई होती तो उसका भार इंडिगो संभाल सकती है, ऐसा पूर्व में उसने किया भी है, लेकिन इंडिगो के स्तर पर हुई खामी का खामियाजा पूरे सेक्टर को उठाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिगो के शीर्ष बोर्ड से लेकर उसके प्रबंधन तक की इसमें गलती है। यह एक बड़ी कंपनी है जिसने बहुत ही सफलता से भारत जैसे विकासशील देश में एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाया है। जब दुनिया की कई एयरलाइनें डूब गईं और भारत में जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा एयरलाइंस, गो इंडिया जैसी दिग्गज एयरलाइनें बंद हो गई तब भी इंडिगो न सिर्फ बनी रही बल्कि समय पर सेवा देकर लगातार मुनाफा भी कमाया है। मगर यहां लगता है कि इंडिगो प्रबंधन शुरू से ही इस मुगालते में रहा कि जब समय आएगा तो वह डीजीसीए को नियमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर लेगा और वह काफी सुस्त रहा। जब बोझ बढ़ने लगा तो उसने ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटों को रद करना शुरू कर दिया और जो फ्लाइटें चलाई जानी थीं, उनमें भी काफी विलंब होने लगा। इससे अफरा-तफरी बढ़ी। यहां पूरी गलती इंडिगो प्रबंधन की ही नहीं, उनके बोर्ड की भी है जिस पर कंपनी के सारे कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। उसके बोर्ड ने न तो डीजीसीए को विश्वास में लिया और न ही दूसरी एयरलाइनों के साथ मिलकर कोई प्रबंध किया। एयरलाइन को नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को समय से पहले सूचना देनी चाहिए थी, यह नहीं किया गया। एविएशन क्षेत्र के नियमों का न्यूनतम पालन भी किया जाता तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। जो भी हो, सालों की मेहनत पर पानी फिर गया और इंडिगो की विश्वसनीयता पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है।

डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का जवाब इंडिगो ने दिया है, क्या उससे संतुष्ट हुआ जा सकता है?

बिल्कुल नहीं। अभी तक जो कारण सार्वजनिक तौर पर आए हैं, वो बेहद बेतुके हैं। एफडीटीएल को लेकर एक वर्ष पुराने नियम हैं। क्या कंपनी को मालूम नहीं था कि उसे कितने नए पायलटों और क्रू की जरूरत है। यह बहुत ही गंभीर कारपोरेट गवर्नेंस का मामला है। क्या कंपनी के प्रबंधन ने अपने बोर्ड को बताया था कि उन्हें कितने नए पायलटों की जरूरत है और कितनों की भर्ती की जा रही है। क्या इस बारे में समय-समय पर जानकारी दी गई। पायलटों की खरीद आप शापिंग माल में नहीं कर सकते। उनकी भर्ती प्रक्रिया लंबी चलती है, फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। और यह देखिए कि नए पायलट भर्ती नहीं कर रहे थे लेकिन सर्दियों के सीजन (अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026) के लिए ज्यादा उड़ानों की प्लानिंग भी कर ली। यह भी तब हुआ जब नवंबर, 2025 में एयरलाइन की औसतन 40 उड़ानें रोजाना रद हो रही थीं। यह सामान्य बात नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह हिमालय जैसी बड़ी गलती है इंडिगो की।

● क्या डीजीसीए को एक नियामक के तौर पर और मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी?

अब जबकि घटनाक्रम हो चुका है और हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो यह कहा जा सकता है। लेकिन आप यह मत भूलिए कि उदारीकरण के दौर में किसी भी सेक्टर में निजी कंपनियों के प्रोफेशनल कामकाज में नियामक एजेंसी की तरफ से हस्तक्षेप करने को काफी खराब माना जाता है। यह बात अब सामने आ रही है कि एक दिसंबर, 2025 तक डीजीसीए और इंडिगो की बैठकें हुई हैं जिनमें कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि जिससे लगे कि हालात अगले तीन-चार दिनों में ही हाथ से बाहर हो जाएंगे। मैं इस सेक्टर को बहुत करीब से जानता हूं कि और कभी इस बात का सुझाव नहीं दूंगा कि विमानन कंपनियों के कामकाज में डीजीसीए का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो।

● ऐसे में आगे क्या सरकार को ज्यादा सक्रिय भूमिका में होना चाहिए? कई लोग इस तरह की मांग भी कर रहे हैं कि और एयरलाइनों को प्रोमोट करना चाहिए?

सवाल यह है कि एयरलाइनों को प्रोमोट करने का काम क्या सरकार का है? जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि देश में पांच बड़ी एयरलाइनों की जरूरत है तो क्या सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। यह तो देखना होगा। सरकार जब अपने नियंत्रण वाली एयरलाइन एअर इंडिया को बहुत ही मशक्कत से बेचकर बाहर निकली है तो इस तरह के सवाल का क्या मतलब है? दूसरी एयरलाइनों को प्रोमोट करने के लिए इंडिगो की मौजूदा 65 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को क्या विभाजित किया जा सकता है? इंडिगो ने पिछले 10-12 सालों मे किंग फिशर, जेट एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइनों के यात्रियों को अपने में समाहित किया। आज इसकी 65 प्रतिशत यात्रियों को ढोने की क्षमता किस एयरलाइन में है। इंडिगो ने 1000 नए विमानों का आर्डर दिया है, उनका क्या होगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि एविएशन में पूरी दुनिया में बाजार ही दिशा तय करता है, सरकार बाजार की दिशा तय नहीं कर सकती। लेकिन निश्चित तौर से इस घटनाक्रम से सरकार, डीजीसीए और एविएशन कंपनियों को बहुत ही बड़ा सबक मिला है और उस सबक से सभी के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। इंडिगो को भी यह बताने की जरूरत है कि इस तरह के कुप्रबंधन की कीमत बहुत बड़ी होती है। तभी इस तरह का विवाद फिर पैदा नहीं होगा।

Dainik Jagaran Page No-15

यूरोपीय मुद्रा के लिए आधिकारिक तौर पर यूरो नाम अपनाया गया

1995 में आज ही स्पेन में यूरोपीय परिषद की बैठक में नई यूरोपीय मुद्रा के लिए यूरो नाम को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इसे 1999 में विश्व वित्तीय बाजारों में लेखा मुद्रा के रूप में लांच किया गया। एक जनवरी, 2002 से इसके बैंकनोट व सिक्के प्रचलन में आए।

Dainik Jagaran Page No-15

हवा सिंह ने लगातार 11 बार जीती थी नेशनल बाक्सिंग चैंपियनशिप

हैवीवेट बाक्सर कैप्टन हवा सिंह का जन्म 1937 में आज ही हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती हुए। यहीं उनका परिचय बाक्सिंग से हुआ। 1961 से 1972 तक उन्होंने लगातार 11 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यह रिकार्ड आज भी कायम है। 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में सोना अपने नाम किया। 1986 में भारतीय खेल प्राधिकरण में कार्यभार संभाला और भिवानी बाक्सिंग क्लब की स्थापना में योगदान दिया। इस क्लब ने विजेंदर सिंह समेत ओलिंपिक के लिए कई बाक्सर्स तैयार किए।

Dainik Jagaran Page No-15

एआई सीखने की दौड़ में सबसे आगे निकले भारत के लोग

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय एआई (जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सीखने की दौड़ में दुनियाभर में सबसे आगे निकल गए हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोरसेरा की 2025 लर्नर ट्रेंड्स रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों ने 2025 में 36 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह साफ संकेत है कि भारत का कार्यबल तेजी से डिजिटल और एआई के लिए तैयार हो रहा है। लोगों को एआई स्किल सीखने के फायदे भी मिल रहे हैं। 95% सीखनेवालों ने कहा कि इससे उन्हें करियर में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

हर मिनट में तीन पंजीकरण : रिपोर्ट में भारतीयों के एआई सीखने के ट्रेंड पर भी जानकारी दी गई है। देश में अब हर मिनट जेनएआई कोर्स में तीन पंजीकरण हो रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 3.28 करोड़ शिक्षार्थियों के सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें इस साल जेनएआई भारत में लर्निंग पैटर्न पर हावी रहा।

भारत के पास अवसर: युवा, महत्वाकांक्षी वर्कफोर्स और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ, भारत के पास एआई युग में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने का अनूठा अवसर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तेजी से स्किलिंग की आवश्यकता होगी।

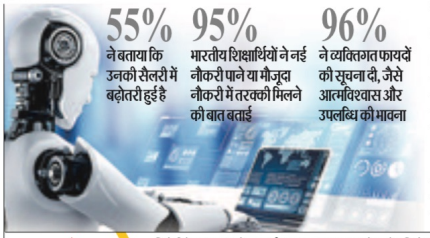

55% ने बताया कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है

95% भारतीय शिक्षार्थियों ने नई नौकरी पाने या मौजूदा नौकरी में तरक्की मिलने की बात बताई

96% ने व्यक्तिगत फायदों की सूचना दी, जैसे आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना

इन कोर्सों की मांग सबसे अधिक

गूगल एआई एसेंशियल्स, जेनरेटिव एआई फॉर एवरीवन जैसे कोर्स इसमें सबसे आगे हैं। भारतीय छात्र डाटा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। यह कौशल विकास सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि नतीजे भी मिल रहे हैं।

भारत में तकनीकी कौशल विकास के लिए शीर्ष 5 क्षेत्र

क्षेत्र	स्किल हासिल करने वालों का प्रतिशत
एआई	73
डाटा एनालिसिस	75
डाटा साइंस	73
मशीन लर्निंग	77
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	72

3.8 करोड़ नौकरियों को बदल देगा एआई

रिपोर्ट के अनुसार जेनएआई 2030 तक 3.8 करोड़ नौकरियों को नया रूप दे सकता है। भारत की जीडीपी में ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। वर्तमान में केवल 3 प्रतिशत कंपनियों के पास ही इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने की प्रतिभा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि अगले पांच सालों में भारत की 38% कोर स्किल्स बदल जाएंगी, इसलिए वर्कफोर्स को तेजी से तैयार करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। भारत में इस पर काफी काम करना होगा।

> तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ, भारत के पास एआई युग में नेतृत्व करने का अनूठा अवसर है। बड़े पैमाने पर स्किलिंग की आवश्यकता होगी।
> **-आशुतोष गुप्ता,** मैनेजिंग डायरेक्टर, कोरसेरा

Hindustan Page No-20

Useful For Mains

शिक्षा की गुणवत्ता और दायित्व का बोझ

शिक्षकों की जिम्मेदारियों को लेकर बहस लंबे समय से चल रही है, विशेष रूप से जब उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य और कार्य संतुलन भी प्रभावित होता है।

देवेंद्रराज सुथार

भारत में शिक्षकों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है, विशेष रूप से तब, जब उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में शुरू की गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया में भी शिक्षकों को बूथ स्तरीय अधिकारी के तौर पर शामिल किया गया है। इसलिए यह बहस नए सिरे से राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गई है। ऐसी खबरें आईं कि काम के दबाव से कई बूथ स्तरीय अधिकारियों की मौत हो गई। जिनमें हृदयाघात, तनाव और आत्महत्या जैसे कारण बताए गए। ये घटनाएं केवल व्यक्तिगत त्रासदियां नहीं, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या का संकेत हैं, जो बताती है कि देश में शिक्षा के संवाहक कहे जाने वाले शिक्षकों को प्रशासनिक प्रणाली के सामान्य कर्मियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि शिक्षकों का सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और कार्य संतुलन भी प्रभावित होता है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में रंगमाटी पंचायत की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान हो गई। गुजरात में एक शिक्षक ने पत्र लिखकर कहा कि वे लगातार थकान और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, इस कारण पुनरीक्षण कार्य को आगे जारी नहीं रख सकते। इस तरह मध्य प्रदेश में एक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम सौ मतदाताओं का सर्वेक्षण करने का लक्ष्य दिया गया था और लापरवाही के आरोप में निलंबन के अगले दिन उनका निधन हो गया। इन घटनाओं से यह सवाल अधिक मुखर होकर सामने आता है कि क्या शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका प्रशासनिक कार्यों के बोझ तले दब गई है! यह पहली बार नहीं है जब चुनावी या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को जीवन की कीमत चुकानी पड़ी हो। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कई मतदान कर्मचारियों की लू से मौत हो गई थी, जिनमें शिक्षक भी शामिल थे।

ये घटनाएं संकेत देती हैं कि समस्या आकस्मिक या व्यक्तिगत स्तर की नहीं, बल्कि संरचनात्मक और प्रबंधन की गंभीर कमी से उपजी है। शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र के भविष्य का उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। मगर वास्तविकता यह है कि शिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल कार्य, यानी शिक्षण में अपेक्षित समय और ऊर्जा नहीं लगा पाता है। उन्हें चुनावी सेवाओं, जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, आधार सत्यापन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी और छात्रवृत्ति एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में निरंतर लगाया जाता रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की एक अध्ययन रपट के अनुसार, देश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने कुल कार्य समय का करीब उन्नीस फीसद ही वास्तविक शिक्षण कार्य में लगा पाते हैं। उनका शेष समय गैर-शैक्षणिक कार्यों और विद्यालय संबंधी प्रशासनिक गतिविधियों में व्यतीत होता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर समस्याओं में से एक शिक्षक का अपने मूल कार्य से लगातार विचलन है। राजस्थान के उदयपुर जिले में किए गए एक

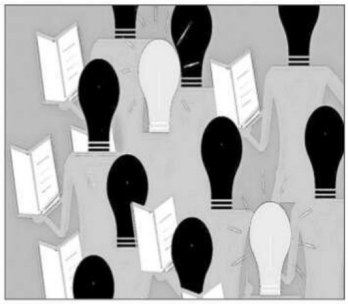

अध्ययन से पता चला कि सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन कक्षा शिक्षण का समय केवल ढाई से तीन घंटे तक सीमित रह गया है, जबकि शेष समय अन्य कार्यों में खर्च होता है। यह स्थिति अभिभावकों को निजी शिक्षण संस्थानों की ओर धकेल रही है, क्योंकि वहां शिक्षक को पूरी तरह शिक्षण कार्य के लिए समर्पित माना जाता है। परिणामस्वरूप सरकारी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कमजोर होती जा रही है।

> कई राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। जब कुल शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त हो और उन्हें अतिरिक्त दायित्व सौंप दिए जाएं, तो समर्पित शिक्षण सामर्थ्य और कम होता जाता है। यदि किसी राष्ट्र को गुणवत्ता आधारित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होती है, तो सर्वप्रथम उसे शिक्षक का सम्मान, सुरक्षा और कार्य संतुलन सुनिश्चित करना होता है। अगर शिक्षकों को उनके मूल कार्य से भटकाकर सतत प्रशासनिक भार का साधन बनाया जाता रहेगा, तो शिक्षा व्यवस्था भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि शिक्षकों को केवल जनगणना, चुनाव में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं तथा आपदाओं से संबंधित राहत कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भी इसी दिशा में निर्देश जारी कर चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में गैर-शैक्षणिक कार्यों को शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या बताया गया है और यह नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि शिक्षकों को उनके मूल कार्य से असंबंधित प्रशासनिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसके बावजूद धरातल पर स्थिति भिन्न है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह समस्या कुछ अन्य देशों में भी मौजूद है। पाकिस्तान में भी शिक्षकों को चुनावी एवं अन्य सरकारी अभियानों में लगाया जाता है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिलीपींस ने वर्ष 2016 में एक कानून बनाकर चुनावी कार्य को शिक्षकों के लिए अनिवार्य से स्वैच्छिक कर दिया और उनके लिए विशेष लाभ, जैसे मृत्यु एवं स्वास्थ्य बीमा, अतिरिक्त अवकाश तथा बेहतर मानदेय की व्यवस्था बनाई। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र कर्मचारी और स्वयंसेवक नियुक्त होते हैं। वहां शिक्षक का उद्देश्य केवल शिक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों का संप्रेषण माना जाता है, न कि चुनाव प्रक्रिया के लिए श्रमिक के तौर पर कार्य करना।

भारत में समस्या की जड़ यह है कि शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ या ज्ञान संवाहक के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी के रूप में देखा जाता है। इसी मानसिकता के कारण उनका व्यापक उपयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इस दृष्टि में बदलाव नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों के बिना संभव नहीं है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किए बिना देश में शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाना मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव समेत अन्य कार्यक्रमों या अभियानों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित किए जाएं, ताकि शिक्षकों को केवल तभी जिम्मा सौंपा जाए, जब स्थिति अत्यधिक अनिवार्य हो। दूसरा, यदि किसी परिस्थिति में शिक्षकों को ऐसे दायित्व निभाने पड़ें, तो उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, उचित मानदेय, कार्यदिवस संतुलन और बीमा जैसे प्रावधानों को अनिवार्य बनाया जाए। तीसरा, राज्य सरकारों और प्रशासनिक तंत्र को शिक्षा के अधिकार कानून का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही विद्यालयों में लिपिक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ शिक्षकों पर न पड़े।

एक और महत्त्वपूर्ण पहलू शिक्षकों के अभाव का है। कई राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। जब कुल शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त हो और उन्हें अतिरिक्त दायित्व सौंप दिए जाएं, तो समर्पित शिक्षण सामर्थ्य और कम होता जाता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, विकासशील देशों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुपस्थिति 11-30 फीसद तक है। भारत में यह अनुपस्थिति कई बार विद्यालय से शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए बुलाए जाने के कारण होती है। यदि किसी राष्ट्र को गुणवत्ता आधारित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होती है, तो सर्वप्रथम उसे शिक्षक का सम्मान, सुरक्षा और कार्य संतुलन सुनिश्चित करना होता है। अगर शिक्षकों को उनके मूल कार्य से भटकाकर सतत प्रशासनिक भार का साधन बनाया जाता रहेगा, तो शिक्षा व्यवस्था भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी।

Jansatta Page No-6

विश्व परिक्रमा

पाकिस्तान : दो विश्वविद्यालयों में शुरू हुआ संस्कृत पाठ्यक्रम

जनसत्ता संवाद

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दो विश्वविद्यालयों ने विभाजन के बाद पहली बार साझा विरासत का हवाला देते हुए संस्कृत में लघु पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और भविष्य में गीता व महाभारत पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पंजाब लाहौर विश्वविद्यालय (सरकारी) और लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय (निजी) ने इस शास्त्रीय भाषा में तीन महीने का पाठ्यक्रम शुरू किया है।

शिक्षक भविष्य में शोध के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में मौजूद संस्कृत पांडुलिपियों के महत्त्वपूर्ण संग्रह पर निर्भर हैं। इन पांडुलिपियों को संजो कर रखा गया है। लघु अवधि के पाठ्यक्रमों की तैयारी पिछले वर्ष शुरू हो गई

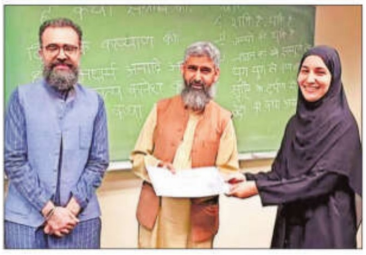

थी लेकिन इस पहले पाठ्यक्रम में प्रवेश 2025 में शुरू हुआ। शिक्षकों के मुताबिक, कई छात्रों ने संस्कृत के पाठ्यक्रमों में रुचि दिखाई है।

पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर डां अशोक कुमार ने बताया, 'लाहौर यूनिवर्सिटी आफ मैनेजमेंट साइंसेज (एलयूएमएस) ने सबसे पहले बुनियादी स्तर-प्रथम और द्वितीय की शुरुआत की, जिसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर ने भी इसे शुरू किया।'

कुमार ने बताया, 'यह पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषा का बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है। संस्कृत पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए एक छात्र को सात स्तर पूरे करने होंगे, जिसमें कम से कम तीन साल लगेंगे।' उन्होंने बताया, 'देखते हैं कि क्या विश्वविद्यालय कभी शास्त्रीय भाषा को समझने के लिए तीन वर्षीय पूर्ण पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है।' प्रोफेसर ने यह भी बताया कि शास्त्रीय भाषा के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थी गीता और महाभारत पढ़ सकेंगे।

Jansatta Page No-7

शोध

कुपोषण : 5 वर्ष की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते 10 लाख बच्चे

जनसत्ता संवाद

दुनिया के कई देशों में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। कुपोषण के कारण ठिगनापन और कमजोरी से बच्चों की मौत बढ़ रही है। 'ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज' की रपट के अनुसार, कुपोषण और अवरुद्ध विकास के कारण हर साल 10 लाख बच्चे अपनी पांचवीं वर्षगांठ से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां बच्चों की मौत का मुख्य कारण कुपोषण और संक्रमण है। भारत में कुपोषण के शिकार दुनिया के करीब आधे बच्चे हैं, जो बेहतर भविष्य के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रपट के मुताबिक, भारत देश में अभी भी पांच वर्ष से कम उम्र के 2.19 करोड़ बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई की तुलना में कम है। मतलब की देश के 18.7 फीसद बच्चे ठिगनेपन का शिकार हैं। रपट के मुताबिक बचपन में पर्याप्त विकास न हो पाने की वजह से 2000 में 27.5 लाख बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि 2023 में यह आंकड़ा घटकर 8.8 लाख पर पहुंच गया।

इसका सबसे ज्यादा असर उप-सहारा अफ्रीका में दर्ज किया गया, जहां पर्याप्त विकास न हो पाने की वजह से 6.18 लाख बच्चों की मौत दर्ज की गई, वहीं दक्षिण अफ्रीका में यह आंकड़ा 1.65 लाख दर्ज किया गया है। इस बारे में ताजा अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल 'द लैंसेट चाइल्ड एंड अडोलेसेंट हेल्थ' में प्रकाशित हुए हैं। अवरुद्ध विकास के तीन अलग-अलग संकेतकों में सबसे बड़ा बोझ कम वजन का है, जो पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौत के 12 फीसद के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद शारीरिक कमजोरी (वेस्टिंग) नौ फीसद, जबकि ठिगनापन (स्टंटिंग) आठ फीसद मौत से जुड़ा है।

पूरी दुनिया में कुपोषण से स्थिति गंभीर है। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। उप-सहारा अफ्रीका में 6.18 लाख बच्चों की मौत दर्ज की गई। दक्षिण एशिया में डायरिया से मरने वाले 79 फीसद बच्चों में शारीरिक विकास अवरुद्ध होने की समस्या पाई गई। सांस संबंधी संक्रमण के मामले में यह आंकड़ा 53 फीसद दर्ज किया गया। इस बारे में अध्ययन के नतीजे जर्नल 'द लैंसेट चाइल्ड ऐंड अडोलेसेंट हेल्थ' में प्रकाशित हुए हैं।

(फाइल फोटो)

अध्ययन में यह भी सामने आया है कि दुनिया में ठिगने बच्चों की संख्या पिछले अनुमान से कहीं अधिक है। शारीरिक रूप से कमजोर और विकास के लिए संघर्ष कर रहे इन बच्चों के लिए मामूली संक्रमण और बीमारियां भी जानलेवा साबित होती हैं। यही वजह है कि 2023 में पांच साल से कम उम्र के करीब आठ लाख बच्चे सांस संबंधी संक्रमणों, जैसे निमोनिया के साथ ही मलेरिया, खसरा और दस्त जैसी बीमारियों का शिकार होकर काल के गाल में समा गए।

उप-सहारा अफ्रीका में स्थिति भयावह है जहां डायरिया सम्बन्धी बीमारियों से मरने वाले बच्चों में 77 फीसद कुपोषण का शिकार थे। वहीं सांस संबंधी संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले 65 फीसद बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर थे।

दक्षिण एशिया में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं, जहां डायरिया से मरने वाले 79 फीसद बच्चों में शारीरिक विकास अवरुद्ध होने की समस्या पाई गई। वहीं सांस संबंधी संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में यह आंकड़ा 53 फीसद दर्ज किया गया। वहीं, समृद्ध देशों में बच्चों में विकास-असफलता से जुड़ी कम मौतें दर्ज हुई। उदाहरण के लिए वहां डायरिया से मरने वाले 33 फीसद बच्चे कुपोषण से जूझ रहे थे। सांस संबंधी संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में यह आंकड़ा 35 फीसद दर्ज किया गया। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता प्रोफेसर बाबी राइनर के मुताबिक, बच्चों में कई कारणों से विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनमें खराब पोषण, भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, गंदगी और युद्ध जैसे कारण शामिल हैं। यह सभी बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं।

Jansatta Page No-7

रिपोर्ट : बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से बढ़ी औसत आयु

एक्सक्लूसिव

■ अरुण चट्ठा

नई दिल्ली। बिहार-यूपी समेत कई राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुधरी जीवनशैली ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है। वहीं, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत आयु लगातार घट रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चार वर्षों में दिल्ली में लोगों की औसत आयु 1.7 वर्ष कम हो गई। हाल में केंद्रीय बैंक ने सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 में औसत आयु से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में औसत आयु में वृद्धि दर्ज की गई है। केरल में औसत आयु सबसे अधिक 75.1 वर्ष है। सबसे कम औसत आयु छत्तीसगढ़ में 64.6 वर्ष है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-19 के मुकाबले 2019-23 में दिल्ली में 1.7 साल और पंजाब में दो साल औसत आयु कम हुई। वहीं, हरियाणा में औसत उम्र 1.1 वर्ष कम हो गई। इस तरह, औसत आयु में गिरावट के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली है। हालांकि, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 0.6 साल बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 70.3 वर्ष की है। औसत आयु कम होने के पीछे विशेषज्ञ प्रदूषण के साथ पानी, बदलती जीवनशैली को मुख्य दोषी मान रहे हैं। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ संजय राय ने कहा कि मौजूदा दौर में जीवनशैली के साथ हवा, भोजन-पानी सब प्रदूषित हो चुका है। हवा और पानी में ऐसे कैंसर कारक तत्व मिले हैं, जिसे कम उम्र में कैंसर हो रहा है। इसलिए प्रदूषण भी जीवन प्रत्याशा कम होने का कारण हो सकता है।-

भारतीय रिजर्व बैंक ने चार वर्षों के आंकड़ों पर जारी की रिपोर्ट

2.4 वर्ष बढ़ गई उत्तर प्रदेश में लोगों की औसत आयु

■ बिहार के साथ उत्तराखंड में भी वृद्धि, प्रदूषण से घट रही दिल्लीवालों की औसत आयु

यूपी में सबसे अधिक बढ़ी औसत आयु

इस दौरान उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की औसत आयु 65.6 वर्ष से बढ़कर 68.0 वर्ष हो गई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 2015-2019 से वर्ष 2019-2023 के बीच औसत आयु 2.4 वर्ष बढ़ गई है। वहीं, उत्तराखंड में 70.6 वर्ष से बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है। वहीं, बिहार में 69.2 से बढ़कर 69.3 वर्ष हो गई है।

राज्यवार औसत उम्र

दिल्ली	74.2 वर्ष
पंजाब	70.8 वर्ष
हरियाणा	68.8 वर्ष
उत्तर प्रदेश	68.0 वर्ष
उत्तराखंड	71.3 वर्ष
बिहार	69.3 वर्ष
झारखंड	69.5 वर्ष

Hindustan Page No-2

संवाद का सौंदर्यबोध

शोभा जैन

आज के महानगरीय जीवन में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। ऐसे व्यस्ततम समय में क्या हमने कभी जीवन में संवाद की भूमिका को समझने की कोशिश की है? वह संवाद ही है, जहां से विचार की दोहरी प्रक्रिया शुरू होती है जो अपने को 'अन्य' की नजर से देखने-समझने की उदारता देती है। हम जिस दौर में हैं, उसमें तकनीक से संवाद का दौर है। लगभग चार दशक पहले तक लोगों में प्रत्यक्ष संवाद करने का हुनर अधिक था। अब वह स्थान अलग-अलग एप पर भेजे जाने वाले संदेशों ने ले लिया है। मगर प्रत्यक्ष संवाद की सीमा भले ही शब्दों में कम पहुंचे, भाव-भंगिमाओं और कहन के प्रभाव और गहराई में अधिक दूर तक पहुंचती है। जब दो व्यक्ति आमने-सामने या साथ होते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तब वह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संवाद नहीं होता, बल्कि समाज के बहुत सारे लोगों के व्यक्तित्व और परिवेश का भी संकेत होता है।

संवाद का यह असर दूर तक जाता है। अगर यह प्रत्यक्ष हो, तब ठीक उसी तरह जैसे गरम दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास-पास एक दूसरे से सटा कर रखे जाएं, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। यानी दूध ठंडा होने लगता है और पानी गरम। ठीक वैसे ही संवाद से बहुत कुछ आदान-प्रदान भी होता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे संवाद में क्या ले रहा है, यह उसकी समझ और परिवेशगत स्थिति पर निर्भर है। दो बुजुर्गों की बातचीत आमतौर पर जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो युवाओं के संवाद लगभग समान विषयों पर। स्त्रियों के क्षेत्र भले ही भिन्न हों, लेकिन मूल बात लगभग समान होती है, जब दो स्त्रियां आपस में संवाद करती हैं। दो परिपक्व पुरुषों के बीच संवाद में भी रीति-नीति का अनुमोदन, समाज, व्यवसाय, भविष्य के विषय हो सकते हैं। दो बुजुर्ग महिलाओं की बातचीत और दो बुजुर्ग पुरुषों की बातचीत के विषय अलग-अलग ही होंगे। हमारे देश में संवाद की कला को लेकर भी अधिक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि संवाद समाज की रीढ़ है।

संवाद वर्चस्व की जड़ता और आतंक को तोड़ता है और समस्या को सरोकार का रूप देकर साझा लड़ाई का मुद्दा बनाता है। आज एक ऐसे दौर में, जब संवाद के स्थान पर विचारधारागत विवाद अपनी पैठ बनाए हुए है, साहित्य हो या राजनीति, धर्म हो या कोई मंच, हमने उस पारंपरिक सोच को सिरे से खारिज या विस्मृत कर दिया, जो संवाद के सौंदर्यबोध से गुजरती है। इसे सामान्य रूप में समझें तो भौगोलिक इकाई से 'राष्ट्र' नहीं बनता। वह बनता है भूखंड की साझा संस्कृति, निर्बाध संवाद से। जिस 'संवाद की कला' की हम बात करते हैं, वह दो समानधर्मी लोगों के बीच ही नहीं, दो अलग-अलग परिवेश के लोगों के साथ भी है। जैसे शिक्षित बुजुर्ग और शिक्षित युवा, अशिक्षित स्त्री और शिक्षित स्त्री के बीच संवाद, ग्रामीण और शहरी स्त्री के बीच संवाद। यह परस्पर संवेदनशील होने का माध्यम भी बन सकता है। इसलिए शायद हम घर के बच्चों को सही संगत के संस्कार भी देते हैं, क्योंकि संगत की प्रारंभिक प्रक्रिया संवाद ही है। संवाद से पहले परस्पर परिचय, परिचय के लिए भी संवाद जरूरी है। संवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ अपने आकलन का और समाज को समझने का बोध भी विकसित करता है। यह भी कि संवाद अनौपचारिक हो। बल्कि सहज रूप में सामान्य चर्चा के रूप में, न कि किसी अकादमिक विमर्श सेमिनार के रूप में।

हर संवाद के अनेक भेद हैं, जिसमें संवेदनशीलता एक आम गुण है, जो बांधने का काम करती है। मगर आजकल यह संवाद 'चैट' या स्मार्टफोन पर संदेशों के आदान-प्रदान में आकर सिमट गया है। जबकि घर से, समाज से नियमित संवाद, साझा गतिविधियां, यह सब केवल बातचीत नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और संबंधों की नींव है। सकारात्मक होने और स्वयं की समझ विकसित करने का एक सकारात्मक विकल्प। कुछ लोग बहुत दायरे में कैद सोच के होते हैं। कभी-कभी स्वयं को अति बुद्धिमान दिखने के लिए भी वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग व्यवहार कुशल न होकर आत्ममुग्ध अधिक लगते हैं, क्योंकि वे संवाद से बचते हैं। उन्हें लगता है कि जब काम हो, तभी किसी से बात की जाए। जैसे दुकानदार से सामान खरीदते समय ग्राहक का उससे संवाद करना मजबूरी है। कुछ लोग इस जरूरत तक ही संवाद करते हैं। अक्सर ऐसे लोग समाज में एक नकारात्मक प्रभाव का कारक भी बनते हैं, क्योंकि उसे दूसरा कोई पक्ष या अनुभव है ही नहीं, सिवाय अपने अच्छे या बुरे अनुभवों के। समाज से कटा हुआ व्यक्ति अनजाने में सही, आत्ममुग्ध अहंकार की हद तक जा सकता है।

स्वस्थ संवाद कभी नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि कभी-कभी भ्रमों और संदेहों का निवारण कर देता है, बशर्ते उसे विवाद की भाप भी न छुए। सम्यक संवाद की भारत में एक दीर्घ परंपरा रही है, इसलिए अतीत में जाकर भी संवाद के प्रभाव और अभाव को तौला जा सकता है। असहमतियों पर भी स्वस्थ संवाद संभव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न विचार होते हैं, उसकी कार्यशैली, प्रतिभा भिन्न। इस भिन्नता को समझे बगैर अपेक्षाओं का अंबार मतभेद को जन्म देता है। अगर स्वस्थ संवाद न हो, तो यह अलगाव एकाकीपन और अवसादग्रस्त होने का कारण बनता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संवाद समझ को विस्तार देता है, जिससे व्यक्ति हिंसक होकर विरोधी बनने के बजाय असहमतियों का भी सम्मान करना सीखता है और सामंजस्य का एक नया विकल्प जन्म लेता है।

दुनिया मेरे आगे

संवाद वर्चस्व की जड़ता को तोड़ता है और समस्या को सरोकार का रूप देकर साझा मुद्दा बनाता है। आज जब संवाद के स्थान पर विचारधारागत विवाद अपनी पैठ बनाए हुए है, साहित्य हो या राजनीति, या कोई मंच, हमने उस पारंपरिक सोच को सिरे से खारिज या विस्मृत कर दिया, जो संवाद के सौंदर्यबोध से गुजरती है।

गहराता संकट

सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही दिल्ली की आबोहवा अब बुरी तरह बिगड़ गई है। इस समय राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है। जहरीली हवाओं से लोग बेहाल हैं। उनमें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। धूल-धुएं से बनी धुंध की दोहरी मार से दृश्यता कमजोर हो गई है। नतीजा यह है कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजधानी में हालात गंभीर हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियां बंद करने का फिर से निर्देश देना पड़ा है। जबकि पिछले महीने ही शीर्ष न्यायालय ने ऐसे आयोजनों पर सवाल उठाया था और इसे रोकने के लिए कहा था। फिर भी खेल गतिविधियां जारी रखी गईं, तो इससे साबित होता है कि लापरवाही किस हद तक बरती जा रही है। यह अदालत के निर्देशों की भी अवहेलना है। जाहिर है कि दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों की सरकारें प्रदूषण को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। हर दूसरे-चौथे दिन फौरी घोषणाएं जरूर की जा रही हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाला जा रहा है।

फिलहाल प्रदूषण को काबू में करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके सार्थक परिणाम नहीं निकल रहे हैं। नतीजा यह कि दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बिगड़ता जा रहा है। दरअसल, इस समस्या के गंभीर लक्षणों की सही मायने में पहचान नहीं की जा रही है। हालात कब तक सुधरेंगे, यह भी कोई नहीं बता रहा। राजधानी में लगातार प्रदूषण बने रहने की असल वजह क्या है, शायद यह कोई जानना नहीं चाहता और अगर कारणों की पहचान है, तो राज्य सरकारें गंभीरता से कदम उठाने से संकोच क्यों कर रही हैं? दिल्ली में अभी अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक है। निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं। ग्रेप-चार के तहत पाबंदियां भी लागू हैं। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर को कम नहीं किया जा पा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस उपाय लागू करने के साथ-साथ लापरवाही के लिए अब संबंधित विभागों की भी जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

आतंक का दायरा

आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी समुद्र तट पर आतंकी हमले से फिर यही साबित हुआ है कि वैश्विक स्तर पर तमाम आतंकरोधी कवायदों के बावजूद अब भी इस समस्या से पार पाना एक बड़ी चुनौती है। हथियारों से लैस पिता और पुत्र ने बोंडी समुद्र तट के पास हनुका नामक कार्यक्रम के लिए जमा हुए यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें पंद्रह लोग मारे गए और कई घायल हो गए। पुलिस के वहां पहुंचने पर हुई मुठभेड़ में एक हमलावर मारा गया और दूसरा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद एक अन्य साधारण व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाल कर एक बंदूकधारी पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली। इस तरह उसने कई लोगों की जान बचा ली। माना जा रहा है कि इस आतंकी घटना के पीछे हमलावरों के भीतर यहूदी विरोध की भावना थी। पिछले कुछ समय से आस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाओं के जोर पकड़ने को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं।

गौरतलब है कि विश्व भर में आतंकी वारदात की प्रकृति में बदलाव आया है और आतंकियों के भीतर आम नागरिकों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके बावजूद आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक खास मौके पर ज्यादा लोगों के जमावड़े वाली जगह पर एहतियाती सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखने की जरूरत नहीं समझी। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि हाल के दिनों में आस्ट्रेलिया में कई स्तर पर नस्लीय आग्रहों के आधार पर हमले और विरोध के मामले सामने आते रहे हैं। यों भी, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर हर समय चाक-चौबंद इंतजाम रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सरेआम अंधाधुंध गोलीबारी की ताजा घटना से साफ है कि सरकार इसमें नाकाम हुई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की निंदा हुई है और आस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर मुसलिम-अरब देशों की ओर से भी आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को खारिज किया गया है। मगर यह भी सच है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और विरोध के बावजूद किसी समुदाय से नफरत की भावना में डूबे लोगों को रोक पाना एक मुश्किल चुनौती है।

गौरतलब है कि इससे पहले इजराइल में लगभग इसी तरह के एक जमावड़े में हमास के आतंकवादियों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर हमला किया था और उसमें बारह सौ से ज्यादा की मौत हो गई थी। उसका अंजाम आज भी हमास और इजराइल के युद्ध और उससे उपजी त्रासदी के रूप में दुनिया के सामने है। इसी प्रकृति के एक अन्य हमले में भारत में कश्मीर के पहलगाम में हमलावरों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कई लोगों को मार डाला था। आस्ट्रेलिया के बोंडी समुद्र तट पर हुए आतंकी हमले का एक पहलू बेहद अहम है कि जहां बंदूकधारी हमलावरों की पहचान मुसलिम बताई गई है, वहीं अपनी जान हथेली पर रख कर उनसे भिड़ने और एक हमलावर को रोकने में कामयाब रहा व्यक्ति भी मुसलिम समुदाय से ही है। इसे आतंकवाद के विरुद्ध एक स्वतः स्फूर्त इंसानी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी जरूरत समूची दुनिया में महसूस की जा रही है। दरअसल, आतंकवाद अलग-अलग समुदायों के बीच दूरी और द्वेष को ही अपना जरिया बनाता है। इसलिए इसका सामना करने के मकसद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस रणनीति के समांतर भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और सहयोग के मानवीय मूल्यों को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

भारतीय हितों को बल देने वाला दौरा

श्रीराम चौलिया

पीएम मोदी के जार्डन, ओमान और इथियोपिया के दौरे से आर्थिक-सामरिक लाभ के साथ ही वैश्विक नेतृत्व की भारतीय आकांक्षाओं को भी संबल मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। सतही तौर पर देखें तो लगता है कि इन तीनों देशों का भारतीय विदेश नीति के लिए कोई विशेष महत्व या सुर्खियां बटोरने वाली अहमियत नहीं है। इसके बावजूद सच्चाई यही है कि कूटनीति समाचारों में सनसनी से प्रेरित नहीं होती है। मोदी की विदेश यात्राओं के गंतव्यों का चयन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में जार्डन और ओमान भारत के 'लिंक एंड एक्ट वेस्ट' रणनीति यानी कि पश्चिमी एशिया से जुड़ाव और सक्रिय रिश्ते बनाने की कवायद के लिहाज से अहम हैं। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप में पैठ और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की दृष्टि से इथियोपिया का भी उतना ही महत्व है।

मोदी सरकार ने आर्थिक कूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति में जार्डन के साथ साझेदारी बहुत उपयोगी होगी। भारत पहले से ही जार्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मोदी की यात्रा के दौरान आयोजित हो रहा 'व्यापार मंच' इस साझेदारी को नए आयाम देगा। जार्डन के उर्वरक और परिधान क्षेत्र में भारतीय निवेश काफी बड़ा है और निर्यात में वृद्धि लाने वाले उद्यमों को बढ़ावा देना दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। जार्डन के साथ द्विपक्षीय सहयोग से भी अधिक महत्व क्षेत्रीय सहभागिता में है। जार्डन भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइमेक) का प्रमुख भागीदार है। जार्डन खाड़ी देशों को रेल लाइनों के माध्यम से इजरायल के हाइफा बंदरगाह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जो यूरोप के साथ व्यापार को सुगम बनाता है। दुर्भाग्यवश अक्टूबर 2023 से इजरायल और हमास के बीच घमासान युद्ध के चलते आइमेक को मूर्त रूप देने की योजना में विलंब हुआ है। हाल की गाजा शांति योजना के कुछ हद तक सफल होने के साथ यह उम्मीद बढ़ी है कि आइमेक आखिरकार लागू किया जा सकता है।

एक उदार अरब देश के रूप में जार्डन ने 1994 में ही इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया था। यरूशलम में विवादित अल-अक्सा मस्जिद के संरक्षक के रूप में जार्डन प्रांतीय शांति बहाल करने और आइमेक को शुरू करने में मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। वर्ष 2018 में मोदी और जार्डन के किंग अब्दुल्लाह ने दिल्ली में 1,500 इस्लामी विद्वानों, शिक्षाविदों और मौलवियों को संबोधित किया था और उदार इस्लाम को आगे लाकर अतिवाद और आतंकवाद को खारिज करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस धुरी

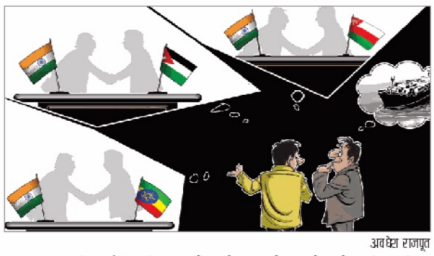

अवधेश राजपूत

पर भारत-जार्डन और करीब आएंगे, क्योंकि जार्डन पाकिस्तान से उत्पन्न हो रहे कट्टरपंथी जिहाद के खतरे से चिंतित है।

ओमान के साथ भारत की पुरानी सामरिक साझेदारी रही है जो खाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले सिरे चढ़ी थी। भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते से द्विपक्षीय कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी। वर्ष 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता करके आर्थिक साझेदारी के मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई थी और ओमान के संग भी वैसी ही आशाएं हैं। याद रहे कि ओमान में भारतीय मूल के लगभग सात लाख प्रवासी रहते हैं और इसी 'मानवीय सेतु' के जरिये पारस्परिक वाणिज्यिक लेनदेन में वृद्धि होगी। प्रारंभिक योजनाओं में तो ओमान आइमेक से बाहर है, लेकिन ओमान के सलालाह, सोहार और दुक्म बंदरगाह अरब सागर तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं। इन्हें होर्मुज से होकर गुजरने वाले जोखिम भरे मार्ग, जहां ईरान और उसके प्रतिद्वंद्वी अक्सर संघर्षरत रहते हैं, के विकल्प के रूप में आइमेक में एकीकृत किया जा सकता है। अप्रैल 2025 में ओमान और नीदरलैंड के बीच विश्व का सबसे पहला 'तरल हाइड्रोजन गलियारा' बनाने की पहल से ओमान स्वचालित रूप से आइमेक के ग्रीन कारिडोर में प्रवेश कर चुका है। भारतीय कंपनियां इन उपक्रमों की हिमायती और लाभार्थी हैं। ओमान भारत का मजबूत रक्षा साझेदार भी है। भारत की तीनों सेनाएं ओमान की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करती हैं। ओमान का दुक्म बंदरगाह भारतीय नौसेना के समुद्री दस्यु विरोधी अभियानों, वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से निपटने के प्रयासों और पश्चिमी हिंद महासागर में सामुद्रिक शक्ति के तौर पर उपस्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारतीय वायु सेना को ओमान से अपने जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त पुर्जे भी मिलने वाले हैं। एक तटस्थ देश के रूप में ओमान भारत को चीन और अमेरिका के अलावा महत्वपूर्ण तीसरे बड़े खिलाड़ी के रूप में देखता है, जो उसकी विदेश नीति को संतुलित करने में मदद करेगा। यह विचार भारतीय रणनीति से मेल खाता है, क्योंकि भारत खाड़ी में स्वयं को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में लगा है।

इथियोपिया की बात करें तो भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वह भारत को शुल्क मुक्त निर्यात करके कारोबार बढ़ाने का इच्छुक है। भारतीय कंपनियां वहां के शीर्ष तीन विदेशी निवेशकों में शामिल हैं। दवा एवं परिधान क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति निरंतर बढ़ने पर है। विनिर्माण में भी भारतीय कंपनियां खासी सक्रिय हैं, जो वहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करती हैं। अफ्रीका में उद्योगीकरण और कौशल विकास के अभाव की पूर्ति भारत कर रहा है, जो चीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के शोषक और कर्ज के जाल में फंसाने वाले उत्पीड़क देश के रवैये से उलट है। इथियोपिया में ही अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है और वह ब्रिक्स का भी पूर्ण सदस्य बन चुका है। वर्ष 2011 में इथियोपिया पहले ही भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है और अदीस अबाबा में मोदी की उपस्थिति अगले शिखर सम्मेलन की नींव रखेगी। एक तथ्य यह भी है कि भारत-अफ्रीका वार्षिक व्यापार 100 अरब डालर का आंकड़ा पार कर चुका है और अब नई पहल इसे और विस्तार देगी। कुल मिलाकर, मोदी इन तीन देशों के दौरे पर एक तीर से कई निशान लगा रहे हैं। इन यात्राओं से प्राप्त संचित लाभ पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में भारत के कद को और ऊंचाई देंगे।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-10

अपने ही जाल में पाकिस्तानी जनरल

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

आसिम मुनीर हाल के सालों के सबसे अलोकप्रिय सेनाध्यक्ष हो गए हैं और काफी हद तक विदूषक सी छवि वाले शहबाज शरीफ बराय नाम देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं।

भारत में नागरिक और सेना के बीच रिश्ते 1947 में ही स्पष्टता के साथ निर्धारित हो गए थे और यह तय हो गया था कि सेना नागरिक नियंत्रण में रहेगी। आजादी के बाद दोनों देशों को ऐसा सैन्य नेतृत्व मिला, जिसने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं एक जैसी थीं, पर सौभाग्य से कोई भारतीय जनरल उस खेल में नहीं पड़ा, जिसने पाकिस्तानी समाज और राष्ट्र-राज्य को लगभग नष्ट कर दिया।

पाकिस्तान के सबसे सम्मानित दैनिक *डॉन* ने अपने एक संपादकीय में देश के अंदर के हालिया घटनाक्रम पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है कि यह तो होना ही था। इतना भर अनपेक्षित है कि नाटक का पटाक्षेप जिस शक्ल में हुआ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन देश की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख को एक ऐसा खेल खेलने के लिए सजा मिल जाएगी, जो फौजियों का सबसे प्रिय शगल है और जिसे वे आजादी के फौरन बाद से ही अपने बनाए नियमों के मुताबिक खेलते आए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को एक फौजी अदालत से चौदह साल की कैद-ए-बामशक्कत इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके जमीनों पर कब्जे किए या अपने विरोधियों को अवैधहिरासत में रखकर शारीरिक यातनाएं दीं, उन्हें सजा देने का आधार राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना बताया गया।

डॉन के अलावा सोशल मीडिया ऐसी बहसों से भरा पड़ा है, जिनमें उन नियमों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिनके अंतर्गत आईएसआई में सेवा कर चुका कोई अधिकारी रिटायर होने के बाद दो वर्ष तक किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। पूछा जा रहा है कि यदि सेवा-मुक्त अधिकारी को राजनीति में भाग लेने के लिए सजा दी जा सकती है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो सेवा में रहते हुए भी देश की चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं? याद रहे, पाकिस्तान में चार बार सेना ने तख्तापलट किया है और जब सीधे तौर पर सत्ता की बागडोर उनके हाथों में नहीं भी रही, उनकी उंगलियां पर्दे के पीछे से नेताओं को कठपुतलियों की तरह नचाती रही हैं।

यह एक वैध तर्क हो सकता है कि सेना का नेतृत्व नहीं चाहता था कि दुनिया को उन करतूतों का पता चले, जिनमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपने सेवाकाल में लिप्त रहते हैं। फैज हमीद ने पत्रकारों के अपहरण करवाए, डेवलपर्स की संपत्तियों पर कब्जा किया, लोगों से सुरक्षा के नाम पर चौथ वसूली की, जिनमें से बहुत से मामलों में उनके रिटायरमेंट के बाद पीड़ित बयान देने के लिए सामने भी आए, पर इन मामलों में सजा देने का मतलब यह स्वीकार करना होता कि फौज के बड़े अफसर भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, इसीलिए फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद अनिवार्य दो साल समाप्त हुए बिना ही राजनीति में शरीक होने का आरोप लगाया गया।

फैज हमीद की सजा को शून्य में नहीं देखा जा सकता। इसे पाकिस्तानी सेना में शीर्ष नेतृत्व की आपसी उठापटक और घरेलू राजनीति में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की दखलंदाजी से जोड़कर समझा जाना चाहिए। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर रिटायरमेंट के एक दिन बाद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) द्वारा एक सौदेबाजी के तहत सेनाध्यक्ष बनाए गए थे। इस नियुक्ति के एवज में उन्होंने शरीफ परिवार के खिलाफ सारे आपराधिक मामले खत्म कराए और 8 फरवरी, 2024 को हुए चुनावों में अभूतपूर्व धांधलियों के जरिये इमरान खान की पार्टी पीटीआई को हरवाकर शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक साझा सरकार भी बनवा दी। उन्हें पुराने हिसाब भी चुकाने थे, इसलिए न्यायपालिका को साधकर उन्होंने इमरान को एक मामले में 14 साल की सजा भी दिलवा दी है। तमाम विवादास्पद संविधान संशोधनों द्वारा उन्होंने न सिर्फ खुद को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना लिया है, वरन ऐसे प्रावधान करवा लिए हैं, जिनके चलते वह जीवन भर फौजी तमगे लगाएंगे और उन पर कभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

आज स्थिति यह है कि जनता में सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में हैं, जनरल से फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर हाल के सालों के सबसे अलोकप्रिय सेनाध्यक्ष हो गए हैं और काफी हद तक विदूषक सी छवि वाले शहबाज शरीफ बराय नाम देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इमरान खुद 2017 में फौज के कंधे पर चढ़कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे, पर अब उनकी छवि सेना के चंगुल से लोकतंत्र को निकाल सकने में समर्थ राजनेता की बन गई है। सेना उन्हें नेपथ्य में धकेलने की जितनी कोशिश करती है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाती है।

अपना कार्यकाल साल 2030 तक बढ़ाकर मुनीर ने खुद को एक विकट स्थिति में फंसा लिया है। दरअसल, फौज में इमरान खान और फैज हमीद के समर्थकों की एक बड़ी संख्या है, जो किसी खामोश तूफान की तरह अपने मौके का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैसाखियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही। यह किसी से छिपा नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह आर्थिक मामलों में भी अंतिम फैसला फौज ही करती है, इसलिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का ठीकरा भी उसी के सिर पर फूटेगा।

उधर, पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान के बीच सशस्त्र झड़पें लगभग रोज हो रही हैं। जिन तालिबान को बड़े जतन से पाक फौज ने पाला-पोसा था, वही अब भस्मासुर की तरह उसे चोट पहुंचाने में लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच सैनिक झड़पों को रोकने के लिए तुर्की, कतर या सऊदी अरब जैसे मित्र इस्लामी राष्ट्रों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि हर महत्वपूर्ण मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार अपने हाथों में रखने वाली सेना के सिर पर ही असफलताओं का ठीकरा भी फूट रहा है।

फैज हमीद के कोर्ट मार्शल और देश के बिगड़ते हालात ने स्पष्ट कर दिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक ऐसे शेर पर सवारी कर रहे हैं, जिस पर चढ़ना तो आसान था, पर उतरना सवार के हाथ में नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह शांतिपूर्ण रिटायर जिंदगी बिता पाएंगे या भविष्य उनके लिए भी पिछले तानाशाहों की ही तरह अपमानजनक और बेरहम होगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page No-14